www.dhyeyaias.com

अप्रैल 2020 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 कोविड-19 का कृषि पर प्रभाव
एक विश्लेषण

2 निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की परीक्षा की घड़ी

3 भारत-चीन संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ

4 महामारी के समय एक वैश्विक नेतृत्व का अभाव

5 जैविक हथियार सम्मेलनः मजबूत सहभागिता की आवश्यकता

6 कोरोना वायरस और अवैध वन्यजीव व्यापार

7 कोविड-19 : मानव और प्रकृति के बीच पुर्नसंयोजन की माँग

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

क्या करें और क्या ना करें

क्या करें

- बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ प्रत्यक्ष रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें
- छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें
- अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

क्या न करें

- यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो, तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें
- अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूएं
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं. +91-11-2397 8046 पर कॉल करें या ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

ध्येय IAS
एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect7

एक परिचय

कुरबान अली

प्रधान संपादक

ध्येय IAS

आशुतोष सिंह

प्रबंध सम्पादक

ध्येय IAS

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 'PERFECT 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय टीम को मेरी शुभकामनाएँ। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा प्रकाशित 'PERFECT 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है। इसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dhyeyaias.com और यूट्यूब चैनल देखें।

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'PERFECT 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'PERFECT 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंतत: उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'PERFECT 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'PERFECT 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

आपके द्वारा दिये गए सुझाव और माँग को ध्यान मे रखते हुए हम रंगों के इस त्यौहार होली के सुअवसर पर 'PERFECT 7' के रंगीन संस्करण की शुरूआत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस नवीन संस्करण से आप सभी छात्रों में नवीन ऊर्जा का संचार हो, साथ ही ध्येय IAS से आपका प्रेम एवं स्नेह सदैव बना रहे।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	•विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	•क्यू.एच.खान
मुख्य संपादक	•कुरबान अली
प्रबंध संपादक	•आशुतोष सिंह
संपादक	•जीत सिंह •अवनीश पाण्डेय •ओमवीर सिंह चौधरी •रजत झिंगन •शशिधर मिश्रा
संपादकीय सहयोग	•प्रो. आर. कुमार •बाघेन्द्र प्रताप सिंह
मुख्य लेखक	•अजय सिंह •अहमद अली •गिर्राज सिंह तोमर •धर्मेन्द्र मिश्रा •रमा शंकर निषाद
लेखक	•अशरफ अली •विवेक शुक्ला •स्वाति यादव •हरिओम •अंशु •सौम्या उपाध्याय
मुख्य समीक्षक	•रंजीत सिंह •रामयश अग्निहोत्री •राजहंस सिंह
त्रुटि सुधारक	•संजन गौतम
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	•गुफरान खान •राहुल कुमार
प्रारूपक	•विपिन सिंह •रमेश कुमार, •कृष्णा कुमार •निखिल कुमार
टंकण	•कृष्णाकान्त मण्डल
लेख सहयोग	•मृत्युंजय त्रिपाठी •बाघेन्द्र प्रताप सिंह •स्नेहा तिवारी
कार्यालय सहायक	•हरीराम •संदीप •राजू यादव •शुभम •अरुण त्रिपाठी •चंदन

Content Office
ध्येय IAS®
most trusted since 2003
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House
Near Chawla Restaurants
Dr. Mukherjee Nagar
Delhi-110009

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अप्रैल 2020 | अंक ⊙ 02

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 1–12
- कोविड–19 का कृषि पर प्रभाव: एक विश्लेषण
- निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की परीक्षा की घड़ी
- भारत–चीन संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ
- महामारी के समय एक वैश्विक नेतृत्व का अभाव
- जैविक हथियार सम्मेलन: मजबूत सहभागिता की आवश्यकता
- कोरोना वायरस और अवैध वन्यजीव व्यापार
- कोविड–19 : मानव और प्रकृति के बीच पुर्नसंयोजन की माँग

7 ब्रेन बूस्टर्स 13–19
7 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 20–21
7 महत्वपूर्ण खबरें 22–24
7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 25
7 महत्वपूर्ण तथ्य 26
7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ 27

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly News Paper

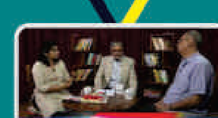

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. कोविड-19 का कृषि पर प्रभावः एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

- वर्तमान में चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन से सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों को नुकसान हो रहा है।
- कई संवेदनशील वर्गों में से एक वर्ग किसानों का भी है जिन्हें लॉकडाउन की वजह से कई मुश्किलों का सामान करना पड़ रहा हैं। इससे कृषि क्षेत्र मुश्किलों में फँस सकता है।

परिचय

- भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर काफी निर्भर है। हालांकि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान अपेक्षाकृत कम है किन्तु भारत की आधे से अधिक आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं इससे सम्बद्ध गतिविधियों में संलग्न है।
- भारत को गांवों का देश कहा जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।
- भारत में कृषि क्षेत्र न सिर्फ यहाँ की विशाल आबादी की खाद्य जरूरतों की पूर्ति करता है बल्कि यह निर्यात का भी अवसर उपलब्ध कराता है। कोविड-19 की महामारी से पूरा विश्व त्राहिमान है और कुछ देश अपनी खाद्य जरूरतों हेतु भारत की ओर भी देख रहे हैं।

कोविड-19 व लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

- लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बागवानी (Horticulture), सब्जी आदि फसलों को हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन से आपूर्तिश्रृंखला बाधित हुई है और ये फसलें बाजार तक समयानुसार नहीं पहुँच पायी हैं। गौरतलब है कि बागवानी, सब्जी आदि फसलों का जीवन काल छोटा होता है और ये जल्दी खराब हो जाती हैं।
- पूरे उत्तर भारत में रबी की फसल (मुख्यत: गेहूँ) पककर तैयार है और इसकी कटाई (Harvesting) बाकी है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से गेहूँ जैसी फसलों की कटाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये फसलें श्रम गहन (Labour Intensive) हैं अर्थात् इनकी कटाई हेतु श्रम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि काफी हद तक प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है और लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरों की गतिशीलता लगभग शून्य है। अत: गेहूँ की कटाई प्रभावित हो सकती है।
- भारत में किसानों ने पिछले कुछ वर्षों से वाणिज्यिक फसलों की खेती में बढ़ोत्तरी की है, किन्तु लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के रोजगार धीरे-धीरे छिन रहे हैं। इस स्थिति में वाणिज्यिक फसलों की माँग निश्चित रूप से कम होगी, अत: इनके मूल्य गिर सकते हैं। ऐसे में पहले से ही घाटे में चल रहा कृषि क्षेत्र और मुसीबत में फँस सकता है।
- फसल और पेट्रोलियम के दाम एक-दूसरे से आपस में संबंधित होते हैं। इस समय वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से भारत में भी पेट्रोलियम के दामों में कमी देखने को मिलेगी, अत: इस स्थिति में फसलों के भी दाम कम हो सकते हैं।
- कोविड-19 व लॉकडाउन के कारण यांत्रिक हार्वेस्टर को चलाने वाले व इसमें लगने वाले मजदूर आदि की कमी के चलते यांत्रिक हार्वेस्टरों को खेतों तक पहुँचाना मुश्किल है।
- वर्तमान की चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारत के निर्यात में लगभग चार से पाँच गुना की गिरावट दर्ज की गयी है। जहाजों के आवागमन न होने के परिणामस्वरूप भारत के चावल निर्यात में भारी गिरावट आयी है। भारतीय चावल के निर्यात में कमी के फलस्वरूप थाईलैंड जैसे प्रतिद्वंदी देशों ने दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में चावल की कीमतों में भारी वृद्धि की है।
- मार्च-अप्रैल के महीनों में आदिवासी समुदाय लघु वन उत्पाद (Minor Forest Produce-MFP) और गैर-काष्ठ वन उत्पाद (Non-timber Forest Produce-NTFP) एकत्र करते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में ये उत्पाद भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।

नोटः लघु वन उत्पाद और गैर-काष्ठ वन उत्पाद में इमली, शहद, तेंदू पत्ता, साल के पत्ते, महुआ के बीज व फूल, करंज के बीज, तेजपत्ता आदि आते हैं। आदिवासी इन उत्पादों को वनों को बिना नुकसान पहुँचाये प्राप्त करते हैं।

भारत में पशुपालन एवं इस पर प्रभाव

- भारत जैसे विकासशील देशों में पशुधन, कृषि का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है। यही कारण है कि भारत की कृषि जीडीपी में पशुधन की 33% से अधिक की भागीदारी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (यूएनएफओ) के मुताबिक भारत में पूरे विश्व की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है।

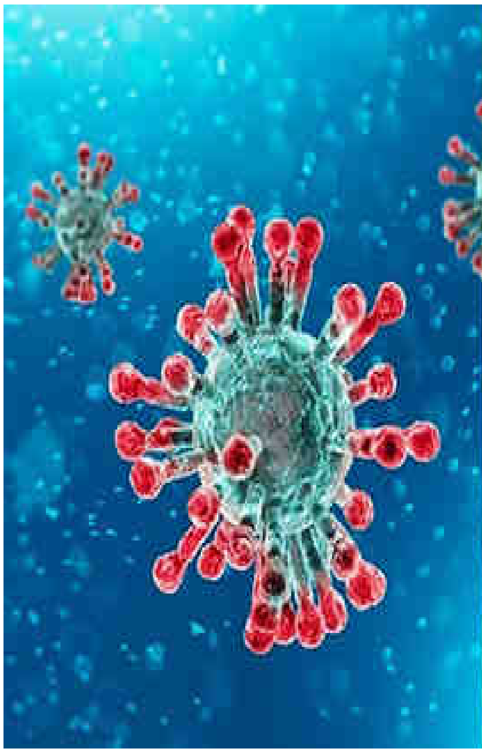

- भारत पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों (यथा- दूध, माँस आदि) का न सिर्फ बड़े पैमाने पर उत्पाद करता है बल्कि इनका भारी मात्रा में निर्यात भी करता है।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैला है अर्थात् यह एक जूनोटिक वायरस है, अतः इसी के चलते भारत में डर के कारण पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- आज एग्रीबिजनेस के तहत सुअर, मुर्गी, मछली, बकरी, भैंस आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही इनकी तीव्र ग्रोथ व बीमारी आदि के कारण इन्हें एंटीबायोटिक भी दी जाती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एंटीबायोटिक दवाओं के कारण एग्रीबिजनेस के तहत उत्पादित पशुधन में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, इस स्थिति में ये पशु बैक्टीरिया या वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और जब इन्हें मानव सेवन करता है तब इन वायरस एवं बैक्टीरिया का मानवों में भी स्थानांतरित होने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि वर्तमान में पशुओं के उत्पाद में तेजी से गिरावट आयी है।

सुझाव

- भारत सरकार को राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के साथ मिलकर किसानों को कोविड-19 व लॉकडाउन की स्थिति से उबारने हेतु रणनीति बनानी चाहिए।
- सरकार, किसानों को अगले सीजन हेतु बड़ी मात्रा में सब्सिडी उपलब्ध करा सकती है ताकि उन्हें कृषि आगतों पर कम खर्च करना पड़े।
- प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत किसानों को प्राप्त होने वाली मात्रा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्कीम को बटाईदार किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तक भी विस्तारित किया जा सकता है।
- आदिवासियों को राहत पहुँचाने हेतु वन धन विकास केन्द्र योजना को और अधिक सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- सरकार को मानव स्वास्थ्य एवं पशु स्वास्थ्य के बीच अंतर्सम्बन्ध को सही ढंग से पहचानकर 'सस्टनेबल एनिमल फार्मिंग' पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- राज्यों को एपीएमसी कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता है और व्यापारियों को सीधे किसानों के खेतों से अनाज आदि को खरीदने की आज्ञा दे देनी चाहिए।
- ई-नाम योजना का भी उचित क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- भारत की विशाल आबादी की खाद्य जरूरतों को देखते हुए कृषि क्षेत्र का निरंतर प्रगतिशील बने रहना अति आवश्यक है। कृषि क्षेत्र के उत्थान से न सिर्फ खाद्य आवश्यकता पूरी होगी बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में माँग का भी सृजन होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. भारतीय कृषि को कोविड-19 व लॉकडाउन ने किस प्रकार प्रभावित किया है? इससे निपटने हेतु सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए? चर्चा करें।

2. निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की परीक्षा की घड़ी

चर्चा का कारण

- हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है कि इससे प्रभावित लोगों की मुफ्त में जाँच की जाए, इसके लिए आवश्यक हो तो निजी अस्पतालों की भी सहायता ली जाए।
- उल्लेखनीय है कि भारत में अभी भी सरकारी अस्पतालों की व्यापकता उतनी नही है जितनी की आवश्यकता है इसलिए यह मांग उठ रही है कि निजी अस्पतालों को भी अपने निजी हित त्यागकर सरकार का साथ देना चाहिए।

परिचय

- कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जिसमें विश्व के सभी देश इस महामारी से निपटने के लिए चिकित्सीय समाधान का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारत जैसी बड़ी आबादी एवं विकासशील देश के लिए यह एक चिंता का विषय बन जाता है।
- भारत की चिकित्सा व्यवस्था विकसित देशों की तुलना में समानांतर नहीं है एवं इसका कवरेज भी कम है। ऐसे में निजी चिकित्सा केन्द्र भारत के लिए विकल्प के रूप में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

सार्वजनिक चिकित्सीय क्षेत्र के उद्देश्य

- भारत में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र तीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रणनीतियों को प्रस्तुत करता है।
  - **क्षेत्र (Coverage):** सार्वजनिक चिकित्सा का लाभ, उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से गरीब जनता और अविकसित क्षेत्र तक कैसे पहुँचे।
  - **गुणवत्ता (Quality):** पारम्परिक प्रथाओं को कम कर आधुनिकी तकनीकी के माध्यम से चिकित्सा किस प्रकार सुलभ हो।
  - **लागत (Cost):** सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वह इस बात की निगरानी करे कि निजी क्षेत्र प्रदाताओं (PSP-Private Sector Providers) के द्वारा प्रदान की गई सेवा, उपयोगकर्ता के लिए लागत व शोषण का साधन न बने।

कोविड-19 और भारतीय चिकित्सा प्रणाली

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि कोविड-19 के परीक्षण और उपचार के लिए पीएम-जन आरोग्य योजना (PM-JAY) को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कमजोर एवं गरीब वर्ग भारत सरकार की बीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा को प्राप्त कर सकेंगे, परन्तु इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी अभी तक नहीं दी है।
- छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश, इन चार राज्यों ने निजी क्षेत्र में कोविड-19 का इलाज मुफ्त में करने के लिए नीति बनाई है परन्तु यह पूरे भारत में नहीं है। जबकि वर्तमान में महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्या ज्यादा है।
- कुछ राज्यों ने निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के परीक्षण पर अनुदान (सब्सिडी) देने के नीति बनायी है। कोविड-19 के परीक्षण को केन्द्र सरकार ने 4500 रू. का उच्चतर सीमा निर्धारित किया है परन्तु यह पिछड़े व गरीबों के लिए वहनीय नहीं है।
- भारत अपनी GDP का लगभग 1 प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा पर खर्च करता है। जॉन हॉपकिन्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20,000 वेन्टीलेटर उपलब्ध है। ऐसे में सरकार कोरोना-19 महामारी से युद्ध के लिए निजी चिकित्सा केंद्रों से सहायता लेकर इनकी संख्या बढ़ा सकती है। विश्व स्वास्थ्य शोध संस्था (World health Research Organization) के अनुसार 1.3 बिलियन जनसंख्या वाले देश में कोविड-19 से निपटने के लिए 1 मिलियन (10 लाख) वेन्टीलेटर होना चाहिए। जबकि इनकी संख्या काफी कम है।

अवलोकन

- निजी क्षेत्र दुनिया की अधिकांश स्वास्थ्य प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए 27 उच्च आय वाले देशों में 6 के पास प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र सार्वजनिक स्वामित्व में हैं जबकि 21 देशों में प्राथमिक देखभाल निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा योगदान देते हैं जैसे-दवाएं, चिकित्सा उत्पाद, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी का मूल ढ़ाँचा।
- भारत के निजी क्षेत्र अत्यधिक विषम है। ये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित नहीं होते हैं। निजी क्षेत्र को उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे-लाभ और गैर लाभ के लिए, औपचारिक और अनौपचारिक, घरेलू एवं विदेशी। निजी क्षेत्रों की नीति स्पष्ट न होने के कारण उन पर नियन्त्रण करने का आधार भी नहीं रहता है।
- निजी क्षेत्र की विनियामक प्रणाली समृद्ध होने के कारण वर्तमान परिदृश्य में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र इनकी सहायता ले सकते हैं। 2015 के अध्ययन के अनुसार, सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र में भारत में प्रति 10,000 आबादी पर लगभग 20 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जिसमें 31% एलोपैथिक डॉक्टर, 30% नर्स एवं दाई, 11% फार्मासिस्ट, 9% आयुष चिकित्सक और अन्य 16% हैं। भौगोलिक आधार पर देखें तो उत्तर भारत की स्थिति, दक्षिण भारत की तुलना में तो और निम्न है। यहाँ तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का घनत्व काफी कम है।
- वर्तमान परिदृश्य में भारत में कोविड-19 से भारत जैसे देश में मध्यम या गंभीर मामलों में वृद्धि हुई तो सम्भवतः भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली असमर्थ हो सकती है। इसका मुख्य कारण भारत के सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र में सीमित संसाधन तथा सीमित तकनीकी विशेषज्ञता है। इन चीजों को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और सभी कोविड-19 पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

पहले 10,000 रोज टेस्ट होते थे परन्तु मार्च से 20,000 टेस्ट होने लगें।

- ताईवान: चीन से सटे ताईवान में देखा गया है कि यह कोरोना को लेकर काफी संवेदनशील है। यहाँ संक्रमण केसों की संख्या बहुत कम है। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए सेना बटालियन को सैनेटाइज करने के लिए उतार दिया गया है। स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षकों सभी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य कर दिया गया है।

- जिस तेजी से कोरोना पीड़ितों की संख्या विश्व में बढ़ रही है वैसे अगर भारत में बढ़ी तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सम्भवत: विफल हो सकती है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए भारत को वर्तमान में निजी अस्पतालों की सहायता लेना एक विकल्प हो सकता है, जिससे निजी क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का दोहन हो सके।

सरकारी प्रयास

- इतनी बड़ी महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाएं हैं-
  - केन्द्रीय सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए निजी होटल को कोरोन्टाइन में बदलने की पहल की गई है।
  - निजी व्यावसायिक अस्पताल एवं प्रयोगशाला, कोरोना महामारी की अवधि तक (सीमित समय के लिए) सरकार के नियंत्रण में रहेगें।
  - वर्तमान में भारत सरकार ने 'आरोग्य सेतु एप्प' लांच किया है जिसके द्वारा कोविड-19 से संबंधित बचाव का सलाह दिया जा रहा है।

- मध्यम एवं गंभीर कोरोना पॉजीटिव रोगियों का इलाज निजी अस्पतालो में भारत सरकार के निगरानी में होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय मानक एवं प्रमाणिक इलाज के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
- हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे सस्ता वेन्टीलेटर बनाया है जिसका नाम 'AgVa' है। इसका निर्माण बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है।

कोरोना के विरूद्ध अन्य देश

- स्पेन: कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए स्पेन ने सबसे पहले निजी अस्पताल एवं प्रयोगशालाओं को सीमित अवधि के लिए अपने नियंत्रण में लिया।
- ब्रिटेन: ब्रिटेन सरकार ने कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान पर अधिक दबाव बनाया। कोरोना पीड़ितों को कोरेन्टाइन में रखने के लिए अतिरिक्त बेड और आम संसाधनों को किराए पर मंगाया।
- दक्षिण कोरिया: फरवरी के अंत तक दक्षिण कोरिया चीन के बाद कोरोना केस में दूसरे पायदान पर था। दक्षिण कोरिया ट्रिपल 'T' अवधारणा (Tracking, Testing and Treatment) में तेजी लाया। वहाँ

आगे की राह

- एक अच्छी चिकित्सा सुविधा की पहुँच भारत के कई दूरस्थ स्थानों तक नहीं है। वहाँ छोटे-छोटे केन्द्र बनाकर कोरोना की जाँच एवं इलाज अत्यन्त आवश्यक है।
- भारत को एक राष्ट्रीय नीति निर्माण करने की जरूरत है जिससे सरकारी व निजी संस्थानों में कोविड-19 का मुफ्त में परीक्षण एवं इलाज हो सके।
- राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए निजी अस्पतालों को भी बिना किसी जिनी स्वार्थ के इस बिमारी से लड़ने के लिए सरकार का हरसंभव साथ देना चाहिए, जिससे कि भारत इस बिमारी पर पूर्णत: विजय प्राप्त कर सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. विश्व में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए भारतीय चिकित्सा क्षेत्र कहाँ तक सक्षम है? उल्लेख करें।

3. भारत-चीन संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत और चीन ने COVID-19 महामारी के कारण अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। हालांकि दोनों देशों के नेताओं ने बधाई संदेशों का आदान-प्रदान किया।

परिचय

- भारत एशिया का पहला गैर-साम्यवादी देश था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। आज सीमा मुद्दों जैसी समस्याओं के बावजूद दोनों देशों के मजबूत व्यापारिक संबंध हैं।
- नवंबर 2019 में 70 साल के राजनयिक संबंधों की स्मृति को मनाने के लिए दोनों देश 70 गतिविधियों को अंतिम रूप देने के लिए सहमत हुए। यह निर्णय राष्ट्रपति शी जिंग पिंग और प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया था। 70 प्रसिद्ध गतिविधियों में व्यापार संवर्धन कार्यक्रम, सैन्य आदान-प्रदान और सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां शामिल थीं।
- दोनों देशों ने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने संबंधों को सामान्य रखने संबंधी एशिया की दो उत्थानशील महाशक्तियों के संकल्प को रेखांकित करते हैं।
- गौरतलब है कि 1950 के दशक में, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों' (Five Principles of Peaceful Coeñistence) की वकालत की थी। इस प्रकार 1 अप्रैल, 1950 को भारत-चीन के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित किये गए। हिंदी चीनी भाई भाई" उस समय से एक तकिया कलाम (catchphrase) बन गई है।

भारत-चीन के बीच सहयोग

- **राजनयिक संबंध :** कोरोना संकट के बावजूद दोनों देशों ने कहा है कि उनके संबंध गर्मजोशी से भरे रहेंगे और वैश्विक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव दोनों देशों के आपसी संबंधों पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं का सिलसिला जारी रहा है।
- **अर्थव्यवस्था और व्यापार:** लंबी अवधि के दृष्टिकोण को अपनाते हुए दोनों देशों ने स्थूल आर्थिक मुद्दों पर समन्वय के लिए तथा गरीबी के उन्मूलन में तथा संपोषणीय शहरीकरण के सृजन में संगत विकासात्मक अनुभवों को साझा करने के लिए एक सामरिक आर्थिक वार्ता को भी शुरू किया है।
- वर्तमान में भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार बढ़कर लगभग 100 बिलियन डॉलर (32 गुना) हो गया है। वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाला व्यापार की मात्रा 92.68 बिलियन डॉलर थी।
- 1,000 से अधिक चीनी कंपनियों ने भारत में औद्योगिक पार्कों, ई-कॉमर्स और अन्य क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ाया है, जिसमें 200,000 स्थानीय नौकरियां पैदा हुई हैं।
- भारत में शीर्ष 5 स्मार्टफोन शिपमेंट में से 4, चीनी ब्रांड के स्मार्टफोन भारतीय लोगों में लोकप्रिय हैं।
- भारतीय कंपनियां भी चीन के बाजार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही हैं, जिसमें चीन में लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी निवेश है। भारतीय आंकड़ों के अनुसार, चीन में निवेश करने वाली दो-तिहाई से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं।
- चीन और भारत ने बुनियादी ढांचे, उच्च प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और चिकित्सा पर व्यापक आर्थिक नीतियों का आदान-प्रदान करने और व्यावहारिक आर्थिक और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक-आर्थिक संवादों के 6 दौर आयोजित किए हैं।
- **विज्ञान और तकनीक:** चीन और भारत ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सहयोगात्मक नवाचार और निवेश के मुद्दों पर गहरी रुचि दिखाई है। भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 आईटी कॉरिडोर स्थापित किए हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च प्रौद्योगिकी में चीन-भारत सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

- चीन और भारत ने नीति समन्वय और सूचना साझाकरण को मजबूत करने के लिए चीन-भारत संयुक्त समिति की 6 दौर की बैठकें आयोजित की हैं साथ ही वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग को भी बढ़ावा दिया है।
- **रक्षा क्षेत्र:** चीन और भारत ने आपसी समझ और विश्वास बढ़ाने, व "आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को संयुक्त रूप से बेहतर बनाने के लिए हैंड-इन-हैंड (Hand -in-

Hand) नामक अभ्यास 8 बार आयोजित किए हैं।

- **पीपुल-टू-पीपुल एक्सचेंज:** भारत और चीन, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर पीपुल-टू-पीपुल एक्सचेंज जैसा तंत्र बनाने का फैसला किया था। 2020 में चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ वर्ष के साथ ही यह चीन-भारत सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान-प्रदान का वर्ष भी है।
- दोनों देशों ने सिस्टर नगरों (Sister Citie) तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किये हैंफुजियान प्रांत और तमिलनाडु को सिस्टर प्रांतों के रूप में जबकि चिनझोऊ (Quanzhou) एवं चेन्नई को सिस्टर नगरों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- हर हफ्ते दोनों देशों के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली 134 उड़ानें हैं, जिनमें से चीन में भारत के लिए 94 उड़ानें हैं और भारत में चीन के लिए 40 उड़ानें हैं

दोनों देशों के बीच विवाद के मुद्दे

- भारत और चीन के बीच हालिया कुछ वर्षों में आर्थिक संबंधों में सुधार हुआ है लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा के विवादित भागों पर तनाव बरकरार है। भारत और चीन के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध सुधरने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश को लेकर 4,057 किलोमीटर लंबी साझा सीमा पर तनाव बरकरार है। इस क्षेत्र के बारे में चीन का दावा है कि यह तिब्बत का हिस्सा है। इसके अलावा तिब्बती पठार के पश्चिमी छोर स्थित अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर भी विवाद बरकरार है।
- मई 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के अर्जी देने के बाद से चीन इस बात पर जोर देता रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ही एनएसजी में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए। चूंकि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है इसलिए चीन का इस मुद्दे पर भारत के प्रति नजरिया संतोषजनक नहीं है।
- भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है किन्तु चीन ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को कमतर करने का प्रयास करते हुए कई बार कहा है कि इस मुद्दे पर बड़े मदभेद हैं।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China Pakistan Economic Corridor& CPEC) का विरोध भारत करता रहा है। भारत के लिए बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम) गलियारा व्यावहारिक नहीं है, जो ओबीओआर का हिस्सा है और चीन इस पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है। इसके अलावा भारत का मानना है कि ओबीओआर (One Belt One Road) को जिन क्षेत्रों से गुजरना है, उन क्षेत्रों में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता के कारण भू-राजनीतिक खतरों की समस्याएं और भी बढ़ने की आशंका है।

आगे की राह

- वर्तमान में, चीन-भारत संबंध एक नए प्रारंभिक बिंदु पर खड़े हैं और नए अवसरों की शुरूआत कर रहे हैं। दोनों देशों को अपनी हजारों वर्षों की सभ्यताओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और पड़ोसी देशों और उभरते हुए प्रमुख देशों के लिए "परस्पर विश्वास बढ़ाने, सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने, मतभेदों को प्रबंधित करने और सामान्य विकास की तलाश" करने के लिए एक-दूसरे के साथ आने का रास्ता तलाशना चाहिए। दोनों देशों को अतीत से कुछ प्रेरणा लेकर निम्न कदम उढ़ाने चाहिए-
  - नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करें।
  - मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को समझें।
  - पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना।
  - ठीक से मतभेदों का प्रबंधन।
- अतः वर्तमान में भारत, चीन की आर्थिक वृद्धि तथा विराट बुनियादी ढांचा बनाने में उसके रिकॉर्ड की अनदेखी नहीं कर सकता इसलिए बेहतर भविष्य तथा मानव जाति के साझा भविष्य के निर्माण में भारत को चीन के साथ की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सीमा मुद्दों जैसी समस्याओं के बावजूद भारत और चीन के बीच मजबूत संबंध हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

4. महामारी के समय एक वैश्विक नेतृत्व का अभाव

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी आज पूरे विश्व को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, लेकिन इससे निपटने हेतु वैश्विक नेतृत्व अपेक्षाकृत अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है।
- हालांकि अभी हाल ही में जी-20 ग्रुप के सदस्य देशों के बीच वीडियों कांफ्रेंसिंग द्वारा वर्चुअल समिट सम्पन्न हुई, किन्तु विशेषज्ञ इसे नाकामी बता रहे हैं।

परिचय

- कोविड-19 महामारी चीन के वुहान शहर से प्रारम्भ होकर बड़ी तेजी से पूरे विश्व में फैल गयी। आज पूरी मानव सभ्यता को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है।
- विभिन्न देशों ने अपने-अपने यहाँ लॉकडाउन लगा रखा है ताकि सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन किया जा सके और कोविड-19 महामारी से निपटा जा सके।
- आज पूरा विश्व आपस में काफी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसी एक देश में समस्या उत्पन्न होने पर अन्य देश इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण कोविड-19 महामारी ही है।

वैश्विक नेतृत्व के विफल होने के कारण

- विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 की महामारी से निपटने में अभी फिलहाल वैश्विक नेतृत्व विफल नजर आ रहा है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं-
  - विश्व में आज विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी सरकारें हैं, जो वैश्विक हितों को ताक पर रखकर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति में लगी रहती हैं अर्थात् उनके द्वारा संकीर्ण राष्ट्रवाद (Narrow Nationalism) पर अधिक बल दिया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा इसका एक उदाहरण अमेरिका का पेरिस जलवायु समझौता से अलग होना बताया जाता है।
  - वर्तमान में बहुपक्षीय संगठन (यथा-संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि) हाशिये पर चले गये हैं अर्थात् इनकी प्रासंगिकता कम हुई है और ये वैश्विक चुनौतियों से निपटने में विफल साबित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) की विशेषज्ञ एजेंसी 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (डब्ल्यूएचओ) पर ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं कि यह चीन की कठपुतली है। डब्ल्यूएचओ की न सिर्फ क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि उसकी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर भी संदेह है। आज जब डब्ल्यूएचओ को कोविड-19 से निपटने में सबसे आगे होना चाहिए तब इसकी सत्यनिष्ठा (Integrity) पर सवाल उठना काफी दुखदपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि यूएसए एवं अन्य विशेषज्ञों ने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाया है कि उसने चीन पर समय रहते दबाव नहीं डाला कि वह कोविड-19 से संबधित सही जानकारी उपलब्ध कराये।

चुनौतियाँ

- जी-20 ग्रुप की वर्चुअल समिट के दौरान, यह घोषणा की गयी कि कोविड-19 महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए पाँच ट्रिलियन डॉलर का फंड बनाया जायेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह राशि नाकाफी है और कोविड-19 महामारी से सिर्फ पैसा दे करके या लगा करके नहीं निपटा जा सकता है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन को नहीं सह सकती है, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए फिलहाल इसमें राहत की कम उम्मीद दिख रही है।
- अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित नहीं हुई है। इससे बचाव हेतु लोग सामाजिक दूरी का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक दूरी का सही ढंग से लागू कर पाना मुश्किल कार्य है (खासकर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में)।
- वैश्विक नेतृत्व के पास कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु कोई व्यापक योजना नहीं है और न ही इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रयास दिखाई दे रहे हैं।
- विश्व के अधिकांश देशों में स्वास्थ्य ढाँचा काफी खराब स्थिति में है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस से निपटना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

सुझाव

- जी-20 ग्रुप ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ विभिन्न देश कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु आसानी से आपस में सहयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ नौकरशाही वाली बाधाएँ (Bureaucratic Hurdles) नहीं हैं। जबकि इसके विपरीत यूएनओ और डब्ल्यूएचओ आदि संगठनों में काफी ब्यूरोकेटिक बाधाएँ है, जो कोरोना वायरस से तीव्र गति से निपटने में चुनौती उत्पन्न करती हैं।
- विश्व के विभिन्न देशों को चाहिए कि लॉकडाउन के दरम्यान भी जरूरी वस्तुओं एवं सेवाओं (यथा-दवा, खाद्य सामग्री आदि) की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो, क्योंकि इस वैश्वीकरण के युग में एक देश में इनका उत्पादन, विपणन आदि प्रभावित हुआ तो उसका असर अन्य देशों में भी होगा।
- जिन देशों (यथा-चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि) ने कोविड-19 पर काफी हद तक काबू पा लिया, उन्हें अन्य देशों की भी मदद करनी चाहिए क्योंकि यदि कहीं भी कोरोना का संक्रमण बचा रहा तो वह फिर से पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है।
- विश्व के विभिन्न देशों को आपस में प्रमाणिक जानकारी पारदर्शिता के साथ साझा करनी चाहिए, उदाहरण के लिए कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को यदि हाइड्रॉक्सी-क्लोरोक्वीन जैसी कोई दवा फायदा कर रही है तो इसकी जानकारी सभी को उपलब्ध करानी चाहिए।
- अभी विभिन्न देश अपने यहाँ उपचार की दवा विकसित करने में लगे हुए हैं। यदि सभी देश मिलकर इस दिशा में एक साथ आगे बढ़ेगे तो सफलता जल्दी मिल सकती है।
- वैश्विक नेतृत्व को कोरोना वायरस से निपटने हेतु स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं

अन्य विशेषज्ञों की एक वैश्विक प्रशिक्षित सेना (Global Trained Army) तैयार करनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों, विशेषज्ञों आदि की एक देश या क्षेत्र से दूसरे देश या क्षेत्र में आसान गतिशीलता सुनिश्चित करनी चाहिए।

- वैश्विक नेतृत्व को भूख व कुपोषण पर भी पैनी नजर रखनी होगी ताकि इनके द्वारा स्थिति और बिगाड़ने न पाये। गौरतलब है कि विकासशील व गरीब देशों की ग्लोबल हंगर-इंडेक्स में स्थिति काफी निराशाजनक रहती है।

निष्कर्ष

- कोविड-19 जैसी महामारियाँ न तो रंग, जाति, धर्म, लिंग आदि को देखती है और न ही किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह करती हैं। इसलिए आज हमें इस महामारी से निपटने हेतु सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके।
- भारत जैसे देशों को कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु वैश्विक नेतृत्व में आगे आना चाहिए। हालांकि इस दिशा में जी-20 और सार्क संगठन की वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री ने सक्रिय भूमिका निभाकर उल्लेखनीय कार्य किया है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।
- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

प्र. कोविड-19 महामारी से निपटने में अभी तक वैश्विक नेतृत्व ने किस प्रकार की भूमिका अदा की है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

5. जैविक हथियार सम्मेलनः मजबूत सहभागिता की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने विश्व में सामूहिक विनाश के जैविक हथियारों (Biological Weapons) के उत्पादन पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर बल दिया है।

परिचय

- भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 'जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन' (Biological and Toxin Weapons Convention-BTWC) की 45वीं वर्षगाँठ पर कोरोना वायरस और इसके वैश्विक प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जैविक और विषाक्त हथियारों के उत्पादन, वितरण व प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
- विदेश मंत्रालय ने इस पर बल दिया है कि आज विश्व को कोविड-19 (COVID-19) जैसी महामारी से निपटना है तो एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है, इन प्रयासों में से एक बीटीडब्ल्यूसी के प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन करना है।
- ध्यातव्य है कि भारत 'जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन' के सदस्य देशों के साथ मिलकर जैविक और विषाक्त हथियारों से संबंधित डाटाबेस तैयार कर रहा है जो जैव-खतरों और जैव-आपात स्थितियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जैविक और विषाक्त हथियार क्या हैं?

- बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एवं अन्य विषाक्त संक्रमणकारी तत्व जिनका उपयोग युद्ध में नरसंहार के लिए किया जाता है उन्हें जैविक और विषाक्त हथियार के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान में जैविक या विषाक्त हथियार के निर्माण हेतु लगभग 200 प्रकार के जीवाणु, विषाणु, फंफूद एवं अन्य विषाक्त कीटाणु पर्यावरण में मौजूद हैं। एन्थ्रेक्स, प्लेग, बोटड्यूलिज्म, सारमोलेला, टूलेरीमिया, ग्लैन्डर, जैसे खतरनाक जीव इसमें शामिल हैं।
- कई वाहक पाउडर के रूप में होते हैं। इन्हें आसानी से पानी या हवा में छोड़ा जा सकता है या किसी के भोजन में मिलाया जा सकता है। ये 24 घण्टे के अन्दर प्राणी और वन्य जीवों की जान ले सकते हैं।

जैविक एवं विषाक्त हथियारों का युद्ध में उपयोग

- जैविकीय युद्ध के प्रयास के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के अस्सूर साम्राज्य के लोगों ने शत्रुओं के पानी पीने के कुओं में एक विषाक्त कवक डाल दिया था।
- मध्यकाल में मंगोलों द्वारा संक्रमित पशु शरीरों को शत्रु राज्य के जल स्रोतों में डलवाकर संक्रमित करने के कई आख्यान मिलते हैं।
- जैविकीय हथियारों का विकसित रूप में प्रयोग जर्मन सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में एंथ्रेक्स तथा ग्लैंडर्स के जीवाणुओं द्वारा किया गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दरम्यान जापानी फौज ने चीन पर कई जैविक तथा विषाक्त हथियारों से हमला किया था। इससे लाखों नागरिक प्लेग तथा हैजा से पीड़ित हुए थे।
- नाजी जर्मनों के जैविकीय हथियारों के संभावित खतरे का प्रत्युत्तर देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम तथा कनाडा ने सन् 1941 में जैवकीय हथियार विकास करने के संयुक्त कार्यक्रम पर एक साथ कार्य किया तथा एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस एवं बोटुलिनस के विषैले जैव हथियार तैयार किये परन्तु बाद में यह संभावित भय की एक अतिरंजित प्रतिक्रिया ही सिद्ध हुई।
- सन् 2001 में आतंकवादियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एंथ्रेक्स के कई आक्रमण किये गये।

चुनौतियाँ

- यदि ये जैविक हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गये तो इससे समूची मानव सभ्यता को खतरा पैदा हो जायेगा।

- जैविक हथियार का प्रयोग भले ही एक देश या समूह द्वारा दूसरे देश या समूह पर किया जाये, परन्तु इसके दुष्प्रभाव व्यापक क्षेत्र और कभी-कभी पूरे विश्व पर होते हैं।
- जैविक और विषाक्त हथियारों का उत्पादन तो आसान है किन्तु इन्हें सम्भाल कर रखना काफी चुनौतीपूर्ण है।
- जैविक और विषाक्त हथियारों को तैयार करना प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मानव ने जब पर्यावरण में आवश्यकता से अधिक छेड़छाड़ की तो कोरोना, निपाह, बर्ड फ्लू आदि जैसे वायरस जंगली जीवों से मानवों में भी फैल गये।

प्रयास

- जैविक एवं विषाक्त हथियारों के उत्पादन, वितरण व प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु कई वैश्विक सम्मेलन हुए, जिन्हें निम्नांकित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-
  - प्रथम विश्व युद्ध में जैविक हथियारों के घातक परिणामों को देखने के पश्चात् सन् 1925 में विश्व के कई देशों ने जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत बातचीत की ताकि इन हथियारों के उत्पादन व प्रयोग को नियंत्रित किया जा सके।
  - 10 अप्रैल 1972 को कई देशों ने मिलकर 'जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन' (बीटीडब्ल्यूसी) की स्थापना की और यह सम्मेलन 1975 में लागू हुआ। उल्लेखनीय है कि बीटीडब्ल्यूसी जैविक और रासायनिक हथियारों के हर प्रकार के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय संधि थी। इस संधि (या सम्मेलन) पर भारत ने सन् 1973 में हस्ताक्षर किये थे।
- भारत में जैविक एवं विषाक्त हथियारों के मामलों के लिए गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है। गृह मंत्रालय इन हथियारों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर कड़ी नजर रखता है। हालाँकि रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, डीआरडीओ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि भी जैविक व विषाक्त हथियारों के प्रसार को रोकने हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इन हथियारों की चुनौतियों से निपटने हेतु गाइडलाइन जारी की है जिसमें सार्वजनिक एजेंसियों के साथ निजी एजेंसियों की भागीदारी पर भी बल दिया गया है।

आगे की राह

- कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सिद्ध कर दिया है कि जैविक एवं विषाक्त हथियारों के उत्पादन हेतु प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना पूरी मानवता के लिए कितना घातक है। अतः ऐसी महामारियों से निपटने हेतु सभी हितधाराकों को एक प्लेटफार्म पर आना होगा और बीटीडब्ल्यूसी एवं अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल देना होगा।
- आतंकवादियों एवं अन्य अराजक तत्वों के द्वारा जैविक व विषाक्त हथियारों के इस्तेमाल के प्रति सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. "जैविक एवं विषाक्त हथियारों के उत्पादन व प्रयोग ने न सिर्फ प्रकृति के साथ गंभीर छेड़छाड़ को प्रोत्साहित किया है बल्कि पूरी मानव सभ्यता के समक्ष खतरा उत्पन्न किया है।" टिप्पणी करें।

6. कोरोना वायरस और अवैध वन्यजीव व्यापार

चर्चा का कारण

- COVID-19 के स्रोत के बारे में वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अभी भी अनिश्चित हैं। कुछ शोध में चमगादड़ तो कुछ में पैंगोलिन के शरीर में मिले वायरस के जीनोम से कोरोना के जीनोम में समानता पाई गई है। एक तीसरी संभावना यह जताई जा रही है कि कोरोना दो तरह के वायरसों के मेल से बना तीसरा रूप हो सकता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है।

परिचय

- यह सर्वविदित है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में हुई थी और जनवरी 2020 में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, चीन के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक ने कहा था कि "नए कोरोनोवायरस की उत्पत्ति एक वुहान सीफूड मार्केट में अवैध रूप से बेचे गए वन्यजीवों से हुई है।"
- नतीजतन, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को बचाने के लिए वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, और उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा की घोषणा की।
- गौरतलब है कि अवैध वन्यजीव व्यापार को दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अवैध व्यापार गतिविधि के रूप में पहचान की गई है और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के ड्रग्स एंड क्राइम ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक वन्यजीव तस्करी उद्योग का आकार 7 बिलियन यूएस डॉलर से लेकर 23 बिलियन यूएस डॉलर तक है।
- वन्यजीवों का अवैध व्यापार एक आपराधिक गतिविधि है और कई देशों ने वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (CITES) पर देशों के बीच समझौता किया है।

संकटग्रस्त जीवों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय

- CITES (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, CITES और अन्य क्षेत्रीय और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।

- 1975 के इस अभिसमय को विशेष रूप से विश्व के संकटग्रस्त जीवों और पादपों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निर्मित किया गया है। यह जीवित नमूनों तथा अधिसूचित जीवों से प्राप्त किये गये उत्पादनों के व्यापार को नियमित करता है। सीआईटीईएस के अनुच्छेद 1 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण लुप्त होने की कगार पर स्थित 700 जीवों की सूची जारी की गयी है। लेकिन अभी भी तस्करों द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है। संकटग्रस्त जीवों को तस्करी के माध्यम से दूसरे देशों में लाया जाता है, फिर दस्तावेजों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है मानो ये जीव उन क्षेत्रों से आये हो जहां वे प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं।
- भारत इस समझौते के लागू होने के लगभग एक साल बाद 18 अक्तूबर, 1976 को इसमें शामिल हुआ और इस समझौते में शामिल होने वाला 25वाँ सदस्य बना। वर्तमान में CITES के पक्षकारों की संख्या 183 है।

ट्रैफिक (TRAFFIC)

ट्रैफिक WWF (World Wildlife fund) एवं IUCN का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में IUCN के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग द्वारा की गई थी। ट्रैफिक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है।

क्षेत्रीय संगठनों की पहल

- सार्क देशों ने दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान दक्षिण एशिया वन्यजीव व्यापार पहल (SAWTI) की स्थापना की। अवैध व्यापार पर नकेल कसने और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कानूनों के तहत कानूनी रूप से कारोबार किए जा सकने वाले जंगली जानवरों और पौधों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए यह एक बेहतर प्रयास था।
- 9 वीं ईस्ट एशिया समिट में पूरे क्षेत्र में अवैध तस्करी और अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए सामंजस्य, क्षमता निर्माण, समर्थन, समन्वय और संसाधनों में वृद्धि के लिए विचार विमर्श किया गया ।

भारत में क्या है कानून

- भारत में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने की है, ताकि देश में संगठित वन्यजीव अपराधों का मुकाबला किया जा सके। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (जेड) के तहत ब्यूरों को संगठित वन्यजीव आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी आसूचना एकत्र करने और राज्यों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों तक पहुंचाने का अधिकार है ताकि अपराधियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जा सके।

पैंगोलिन सर्वाधिक खतरे मे

- अभी हाल ही में प्रतिष्ठित मेडिकल रिसर्च जर्नल नेचर में प्रकाशित शोध में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया था कि चीन में तस्करी कर लाए गए जानवर पैंगोलिन में कोरोना से मेल खाते वायरस मिले हैं। स्तनपाई जीव पैंगोलिन की चीन में मांस और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल को लेकर सबसे ज्यादा अवैध तस्करी होती है।
- नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध में शोधकर्ताओं ने कहा है कि उनका जेनेटिक डेटा दिखाता है कि ऐसे जानवरों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी और बाजार में इसकी बिक्री और तस्करी पर कड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। चींटिया खाने वाले इस स्तनपायी जीव पैंगोलिन की तस्करी के कारण ही यह विलुप्त होने की कगार पर है।
- पैंगोलिन की खाल एशिया में पारंपरिक चीनी दवाएं बनाने में इस्तेमाल की जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाए जाने वाले पैंगोलिनों पर अतिरिक्त नजर रखने की जरूरत है ताकि कोरोना वायरस के फैलने में उनकी भूमिका और भविष्य में संक्रमण के खतरे के बारे में पता लगाया जा सके।
- पैंगोलिन की 8 प्रजातियों की कमर्शियल बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी है लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में पैंगोलिन की सबसे ज्यादा तस्करी होती है। पारंपरिक चीनी औषधियों के लिए हजारों पैंगोलिन की हर साल तस्करी होती है। चीन, वियतनाम और एशिया के कुछ देशों में इसके मांस को स्टेटस सिंबल से भी जोड़कर देखा जाता है।
- कोरोना वायरस शरीर के द्रव्य, मल और मांस से आसानी से फैल सकता है। इसलिए खाने के लिए पैंगोलिन का इस्तेमाल ज्यादा चिंता की बात है। पैंगोलिन को इसकी स्कैल्स के लिए भी मारा जाता है लेकिन उसके संपर्क में आना मांस की तुलना में कम खतरनाक है।

चुनौतियाँ

- वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने उल्लेख किया है कि जीवित और मृत जंगली जानवरों के लिए अवैध बाजार कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विशेष रूप से चीन, लाआसे, थाईलैंड और म्यांमार के करीब क्षेत्रों में संपन्न हो रहे हैं।
- वन्यजीवों को दुनिया भर में खतरे का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया भर के अवैध बाजारों में इसकी मांग लगातार जारी है, इसके अलावा भारत में वन्य जीवों के अवैध व्यापार में काफी तेजी आई है।
- बाघ, पैंगोलिन, स्टार कछुआ और टाउकेई छिपकली को चुना गया है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवैध व्यापार होने के कारण अस्तित्व खतरे में है। बाघ का उसकी खाल, हड्डियों और शरीर के अंगों के लिए, छिपकली का उसके मीट और उसकी खाल का परम्परागत दवाओं में, स्टार कछुए का मीट और पालने के लिए तथा टाउकेई छिपकली का दक्षिण-पूर्व एशिया खासतौर से चीनी बाजारों में परम्परागत दवाओं के लिए अवैध व्याापार किया जाता है।
- हाल में गैर-कानूनी तरीके से व्यापार करके लाई गई प्रजातियां और उनके विभिन्न अंगों को जब्त करने के संबंध में कई खबरें इस बात का संकेत देती हैं कि हवाई अड्डों के रास्तें तस्करी करके लाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रमुख प्रजातियों में स्टार कछुए, पक्षी, शहतूत, शील, बाघ और तेंदुए के विभिन्न अंग, हाथीदांत, गैंडे के सींग, पैंगोलिन और पैंगोलिन की खाल, सीपियां, समुद्री घोड़ा, सी कुकुम्बर, रेंगने वाले जंतुओं की खालें, जीवित सांप, छिपकलियां, मूंगा और औषधीय जड़ी-बूटियां शामिल हैं।

आगे की राह

- जैव विविधता और जंगलों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले हर प्रकार के गैर-कानूनी वन्य जीव व्यापार को समाप्त करने के लिए जागरूकता पैदा करना, कार्रवाई करना और कानूनों को कड़ाई से लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।

- विकास के नाम पर प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ और शोषण के दुष्परिणाम दिखाई पड़ने लगे हैं। बढ़ते शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण जंगलों की कटान की जा रही है। अवैध खनन के द्वारा प्रकृति की जीवन रेखा नदियों का अस्तित्व मिटता जा रहा हैं। मानव जीवन को सहज बनाने के लिए ईजाद किया गया प्लास्टिक आज जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा है।
- ऐसे समय जब हम प्रजातियों के खोने के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं, वर्ष 2020 एक महत्वपूर्ण साल है-प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्रवाई का स्तर बढ़ाने और टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में अर्थपूर्ण प्रगति के लिए जरूरी है कि सभी देश मिलकर इस दिशा मे कार्य करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. हाल ही में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना महामारी के लिए वन्यजीव तश्करी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस बात से आप कितना सहमत है? चर्चा करें।

7. कोविड-19 : मानव और प्रकृति के बीच पुर्नसंयोजन की माँग

चर्चा का कारण

इस साल का विश्व स्वास्थ्य दिवस ऐसे समय में आया है जब दुनिया कोविड-19 के खिलाफ एक अभूतपूर्व लड़ाई में लगी है, जिसने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है। यह मानवता को न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, बल्कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करने के लिए भी याद दिलाने का अवसर है।

पृष्ठभूमि

- द गार्जियन के अनुसार दुनिया के 199 देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, दुनिया के अधिकांश देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया है या ले रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय यातायात के साथ ही साथ देशों के अंदर का यातायात भी थम गया है। सभी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और खेल गतिविधियां ठप हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक ब्रेक पर है।
- यहां तक कि ज्ञात इंसानी इतिहास में धार्मिक गतिविधियां बंद हैं। वेटिकन में पोप धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र जगह मक्का को धार्मिक यात्रियों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। हिंदुओं के बड़े मंदिरों के साथ ही छोटे-छोटे मंदिर तक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि घातक वायरस राजा या रंक के बीच अंतर नहीं करता है, और न ही यह क्षेत्रों या धर्मो के बीच अंतर को पहचानता है।
- विकसित देशों में स्वास्थ्य के मोर्चे पर खासी प्रगति के बावजूद कोरोना वायरस से उपजी महामारी ने मानव प्रजाति को असहाय कर दिया है।

महामारी और विश्व

- यह किसी दु:स्वप्न से कम नहीं कि जहाँ वर्ल्ड वाइड वेब यानि इंटरनेट ने दुनिया को खोलकर लोगों को आपस में जोड़ दिया था वहीं कोरोना वायरस ने देशों को सीमाएँ बंद करने और अपनी जनता को सामाजिक दूरी का पालन करने पर मजबूर कर दिया है।
- महामारी ने दुनिया को मनुष्य और प्रकृति के बीच के अंतर्संबंध के फिर से जांच करने के लिए एक मौका दिया है। हमें यह पहचानना होगा कि हम अपनी पृथ्वी को पौधों, पक्षियों और जानवरों के साथ भी साझा करते हैं।
- डब्ल्यूएचओ की "वन हेल्थ" की अवधारणा को अपनाना होगा जो मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण को अपनाता है।
- कोरोना वायरस के संक्रमण के पहले तक पूरी दुनिया में पर्यटकों को काफी महत्व दिया जाता था, उन्हें आर्थिक आय का बड़ा जरिया माना जाता था। इस वायरस का संक्रमण मुख्य रूप से पर्यटकों से फैला, ऐसे में आशंका है कि अब शायद ही दुनिया में पर्यटकों का स्वागत पहले की तरह होगा।

भारत का वैश्विक दृष्टिकोण:

- तच्छं योरावृणीमहे । गातुं यज्ञाय। गातुं यज्ञपतये । दैवी स्वस्तिरस्तु न:। स्वस्तिर्मानुषेभ्य:। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। शं नो अस्तु द्विपदे। शं चतुष्पदे ।। शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।।
- यह प्रार्थना प्राचीन भारत के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें प्रकृति का सम्मान किया गया है और सभी जीवित प्राणियों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता को रेखांकित किया है। प्रकृति की पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है क्योंकि देवत्व की अभिव्यक्ति पौधों और जानवरों सहित हर तत्व में दिखाई देती है।
- भारतीय विश्व दृष्टि में, हमारी प्रार्थना न केवल पृथ्वी पर बल्कि आकाश और अंतरिक्ष में भी इस सद्भाव को बनाए रखने के लिए रही है, जैसा कि निम्नलिखित वैदिक श्लोक में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है:
    - द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: । वनस्पतय: शान्तिर्विश्वेदेवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति: सर्वं शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ।। शान्ति: शान्ति: शान्ति:।।
    - (शांति आकाश और अंतरिक्ष में है, शांति पृथ्वी पर है, शांति पानी में है,शांति पौधों और वृक्षों में है, शांति प्रकृति के विभिन्न तत्वों की अध्यक्षता करने वाले देवताओं में है; शांति हमारी चेतना में है; शांति, हर जगह,बाहर और भीतर व्याप्त है। आपके पास वह शांति है जो आपके जीवन को पूरा करती है)।
- महात्मा गाँधी ने काफी उपयुक्त तरीके से कहा था: मैं प्राकृतिक कला को पहचानने की पूर्वजों की शक्ति के विषय में और कला को धार्मिक स्वरूप देने की उनकी दूरदृष्टि के विषय में श्रद्धा भाव रखता हूँ।

भारत में स्वास्थ्य

- वर्तमान में COVID-19 के कारण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में शहरी-ग्रामीण अंतर के

साथ, सार्वजनिक स्वास्थ्य में अधिक निवेश की आवश्यकता को महसूस किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न सूचकांको में खासी प्रगति की है और महत्वपूर्ण संक्रामक रोगों जैसे कि चेचक और पोलियो को खत्म किया है।

- भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष तक बढ़ गई है और संचारी, मातृ, नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों के कारण भारत का रोग भार 1990 से 2016 के बीच 61 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत हो गया है।
- हालांकि, बीते कुछ वर्षों से जीवनशैली में बदलाव के कारण गैर-संचारी रोगों में भारी वृद्धि हुई है। कुछ साल पहले, डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों ने भारत में होने वाली सभी मौतों में से 61 प्रतिशत के लिए हृदय विकारों, कैंसर और मधुमेह आदि को जिम्मेदार बताया है।
- इन गैर-संचारी रोगों पर अंकुश लगाने के लिए योग और ध्यान को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए इन पहलुओं को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए।

सरकारी प्रयास

- आयुष्मान भारत की प्रमुख योजना 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करके और 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके कुछ हद तक स्वास्थ्य समस्या का समाधान कर रही है।
- इसके अलावा भारत में COVID-19 से लड़ने के लिए कई अभियान चलाये जा रहे हैं इनमें मोबाइल हैण्डवाश फेसिलिटी (आंध्र प्रदेश), प्रग्याम ऐप (झारखण्ड), सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप (नागालैंड), टीम 11 अभियान (उत्तर प्रदेश), कोरोना कवच ऐप (भारत सरकार), ब्रेक द चेन अभियान (केरल)।
- इसके अलावा पंजाब पहला राज्य बना जिसने Covid-19 के लिए सर्वप्रथम कर्फ्यु लगाया साथ ही ओडिशा में COVID-19 के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया।

पर्यावरण संतुलन और विकास

- विकास का अर्थ बड़ा घर और गाड़ी; बिजली, पानी और शराब का अधिक उपभोग; कपड़े, गहने या जूतों से भरे कमरे नहीं है। विकास का अर्थ है मानव और प्रकृति के बीच संतुलन। भगवान ने हमारी तरह ही पशु-पक्षी और पेड़-पौधों को भी बनाया है। इनके साथ सामंजस्य बनाकर चलने का काम सृष्टि में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी होने का दावा करने वाले मनुष्य का ही है।
- COVID-19 महामारी ने पारिस्थितिकी असंतुलन के विषय को केंद्र में ला दिया है, पारिस्थितिक संतुलन में पौधों के संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक मुख्य चुनौती है। इस चुनौती का समाधान न कर पाने के कारण है जीवन के संतुलन के लिए प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध चरमरा गया है। यह असंतुलन मनुष्य की लालसावादी मनोवृति से उपजा है।
- जब हम इस आपदा से उबरकर पुन: इसके द्वारा उत्पन्न आर्थिक मंदी और व्यक्तिगत जीवन में उथल-पुथल जैसी वास्तविकता से दो-चार होंगे तब कई सवाल उठेंगे जिनके केंद्र में यही होगा कि क्या ऐसी विपदाओ को रोका जा सकता है? साथ ही विकास मॉडल और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता और हमारे उत्पादन-खपत पैटर्न की अस्थिरता पर भी सवाल उठेंगे।

आगे की राह

- यह समय सभी भारतीयों और प्रत्येक वैश्विक नागरिक के लिए प्रकृति संरक्षण सक्रिय योद्धा बनने का है ताकि पृथ्वी पर मनुष्य और अन्य सभी जीवित प्राणी स्वस्थ रहें और एक सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व का आनंद लें सकें ।
- भारतीय चिकित्सा संघ और चिकित्सा संस्थानों जैसे निकायों को भी लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाना चाहिए। मीडिया को भी सूचनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
- हम जिस हवा में सांस लेते हैं और जो पानी हम पीते हैं वह साफ होना चाहिए। लॉकडाउन के मद्देनजर हवा की गुणवत्ता में भारी सुधार और हाल ही में शहरी स्थानों में भटकने वाले जंगली जानवरों की रिपोर्ट से पता चलता है कि मानव ने किस हद तक पर्यावरण का विघटन किया है।
- हमारी दुनिया परस्पर निर्भर है। हमें इसके संतुलन की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। हमें ज्ञान को ज्ञान से जोड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर पृथ्वी को सुरक्षित बनाना चाहिए जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मानव, वनस्पति और जीव-जंतु सभी की सेहत का ख्याल रख सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार का प्रमुख कारण मानव तथा प्रकृति के बीच सामंजस्य के अभाव को माना जा रहा है। आप इस कथन से कितना सहमत है? चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

1. बी.सी.जी. वैक्सीन

चर्चा का कारण

- हाल ही में न्यूयार्क इंस्टि्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस की ओर से बी.सी.जी टीकाकरण वाली आबादी पर कोरोना वायरस संक्रमण के असर का विश्लेषण करने के लिए एक रिसर्च किया गया था।
- इस शोध के अनुसार जिन देशों में बी.सी.जी वैक्सीन का अपने टीकाकरण कार्यक्रमों में उपयोग किया गया वहाँ कोविड-19 से कम मौतें देखी गयी।

क्या है बी.सी.जी.

- बी.सी.जी. या बेसिल-कैलमेट-गुएरिन तपेदिक (टीबी) रोग के लिए एक टीका है। जिसकी खोज कैलमेट एवं गुएरिन द्वारा की गयी थी तथा 1924 से यह उपयोग में लायी जा रही है।
- बी.सी.जी. वैक्सीन एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, कुष्ठ रोग, और गैर-इनवेसिव मूत्राशय के कैंसर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- सार्वभौमिक बी.सी.जी. नीति वाले देशों में प्रति मिलियन लोगों में 0.78 मौतें हुई।
- जिन देशों के पास कभी भी सार्वजनिक बी.सी.जी. नीति नहीं थी, उनकी मृत्यु दर प्रति मिलियन लोगों में 16.39 थी।
- वैज्ञानिकों के अनुसार बीसीजी वैक्सीनेशन से वायरस इंफेक्शन और सोप्सिम जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है।
- ब्राजील, जापान, दक्षिण अफ्रीका आदि देश जहाँ वैक्सीनेशन बहुत पहले शुरू किया गया था वहाँ कोरोना फैलने का खतरा 10 गुना कम है।
- अमेरिका, इटली, लेबनान, बेल्जियम व नीदरलैंड जहाँ बी.सी.जी. वैक्सीनेशन नहीं हुआ वहाँ कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा है।
- वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस ज्यादा घातक साबित नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्ट्रेन का फर्क है। स्ट्रेन अर्थात वायरस का जेनेरिक वैरिएंट।
- भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा कोरोना के 12 नमूनों की जाँच के शुरूआती रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिला वायरस सिंगल स्पाइक है, जो कोशिकाओं को ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़ पाता है।
- दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, इटली में मिले वायरस ट्रिपल स्पाइक के हैं जो इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालता है।

भारत की स्थिति

- भारत में बी.सी.जी. वैक्सीनेशन बहुत पहले ही किया गया था।
- बी.सी.जी. वैक्सीन द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के कारण शरीर को इम्यूनिटी मिलती है, परंतु देश में बड़ी आबादी कुपोषित व बिमारियों से ग्रसित है। ऐसी आबादी के सामने कोरोना का खतरा ज्यादा है।
- भारत के सामने दूसरी चुनौती बुजुर्गों को कोरोना से बचाये रखना है। देश में 60 साल से ज्यादा उम्र की आबादी 10 करोड़ के आसपास है, ये वो लोग हैं जो 1962 में नेशनल टी.बी. प्रोग्राम शुरू होने से पहले जन्में थे।

2. जियोफेंसिंग

चर्चा का कारण

- हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित कुछ लोगों के क्वारान्टाइन से भागने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के जियोफेंसिंग प्रणाली द्वारा विभिन्न मोबाइल ऐप के विकास की शुरूआत की है।
- सरकार जियोफेंसिंग प्रणाली के माध्यम से कोविड-19 से प्रभावित लोग जो क्वारानटाइन में रखे गये हैं उनपर नजर रख सकती है। विदित हो कि भारत सरकार ने राज्यों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों के तहत जियोफेंसिंग के उलंघन के मामलें में दूर संचार विभाग से निर्दिष्ट मोबाइल फोन नंबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है।

जियोफेंसिंग क्या है?

- जियोंफेंसिंग किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए आभासी परिधि होती है। यह एक स्थान-आधारित सेवा है जिसमें एक ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जीपीएस, आरएफआईडी, वाई-फाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है।
- जियोंफेंसिंग से 300 मीटर की परिधि में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- विदित हो कि कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने हेतु जियोंफेंसिंग प्रणाली का प्रयोग करने वाले राज्यों में केरल पहला राज्य है।
- जब एक मोबाइल डिवाइस या RIFD टैग एक भागौलिक सीमा, जिसे जियाफेंस के रूप में जाना जाता है, के आसपास स्थापित एक आभासी सीमा में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो उस डिवाइस के बारे में उसमें इंस्टाल प्रोग्राम के आधार पर जानकारी ली जा सकती है।

जियोफेंसिंग के उपयोग

- इसका उपयोग सोशल नेटवर्किंग, विपणन (Marketing), दर्शकों की क्रमबद्धता (Audience arrangment), स्मार्ट उपकरण, मानव संसाधन प्रबंधन, टेलीमैटिल्स तथा सुरक्षा आदि में किया जाता है।

जियोफेंसिंग कैसे काम करता है?

- जियोफेंसिंग का उपयोग करने के लिए, एक प्रशासक या डेवलपर को पहले जीपीएस या आरएफआईडी-सक्षम सॉफ्टवेयर में एक निर्दिष्ट स्थान के आस-पास एक आभासी सीमा स्थापित करनी होती है।
- इस सीमा में जब कोइ भी व्यक्ति ऐसे डिजिटल उपकरण को लेकर प्रवेश करेगा तो कंप्यूटर स्वत: उसकी उपस्थिति दर्ज कर लेगा। इस तरह उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।

3. ऑपरेशन संजीवनी

चर्चा का कारण

- भारतीय वायुसेना ने मालदीव में चिकित्सीय आपूर्ति के लिए एक मिशन को अंजाम दिया, जिसका नाम है 'ऑपरेशन संजीवनी'।
- मालदीव हिन्द महासागर का एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण-पश्चिम में है। यहाँ पर परिवहन, कार्गो अथवा एयर द्वारा ही संभव है।

ऑपरेशन संजीवनी

- वैश्विक कोरोना महामारी के कारण सभी देशों का परिवहन एवं व्यापार ठप हो गया है। ऐसे में किसी देश तक चिकित्सीय आपूर्ति बहुत बड़ा कार्य है।
- भारतीय वायुसेना ने मालदीव का भारत में फँसा 6.2 टन का सामान मालदीव तक पहुँचाया।
- मालदीव पहुँचाए गये आवश्यक चिकित्सीय सामान में इन्फ्ल्यूएंजा वैक्सीन, एण्टी वायरस दवा (लोपथोवरि, रायटोनावरि), हृदय रोगियों के लिए दवाएं, उच्च रक्त-चाप से संबंधित दवाईयाँ थीं। यह मालदीव की चिकित्सा प्रणाली को जारी रखने के लिए बहुत आवश्यक थीं।
- इस कार्य के लिए भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस C-130J एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया।
- मालदीव तक सामान पहुँचाने के लिए भारत ने नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और मदुरई से सामान एक जगह एकत्र किया, यह भी एक जटिल कार्य था।

भारत-मालदीव

- मालदीव एक द्वीपीय देश है इसलिए यहाँ पर खाद्य और कई आवश्यक वस्तुओं की कमी रहती है। मालदीव भारत पर आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्भर रहता है।
- इससे पहले मार्च-2020 के प्रथम सप्ताह में भी भारत ने खाद्य व चिकित्सीय वस्तुओं की आपूर्ति की थी।
- 14 मार्च 2020 को भारत ने 14 सदस्यीय 'कोविड-19 रैपिड रिस्पांस टीम' (डॉक्टरों की टीम) भी वहाँ भेजी थी, इस टीम ने वहाँ के पर्यटकों का इलाज किया तथा वहाँ के डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया।
- फरवरी 2020 में भारत, वुहान (चीन) से अपने छात्रों को लाने के समय मालदीव के 9 छात्रों को भी भारत ने सुरक्षित मालदीव पहुँचाया था।
- इससे पहले वर्ष 2014 में मालदीव के पेयजल संकट से निपटने के लिए भारत ने 'ऑपरेशन नीर' का संचालन किया था।
- गौरतलब है कि भारतीय सेना ने सिर्फ मालदीव ही नही बल्कि हरक्यूलिस C-130J एयर क्राफ्ट की मदद से मणिपुर, असम, नागालैण्ड और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सीय वस्तुओं को प्रदान कर रहा है।

भारतीय एयर क्राफ्ट C130J के पूर्व राहत कार्य

- ऑपरेशन राहत-2013 के उत्तराखण्ड आपदा के समय।
- ऑपरेशन संकट मोचन-2016 में दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिको को वापस लाने के लिए।
- ऑपरेशन करुणा-2018 केरल में आई बाढ़ के समय।

आगे की राह

- मालदीव, सार्क के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत का 'ऑपरेशन संजीवनी', सभी सार्क देशों में भारत के विश्वास को बढ़ाएगा।
- भारत चूंकि पड़ोसी प्रथम के नीति पर आगे बढ़ रहा है इसलिए आवश्यक है कि किसी विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। खासतौर पर कोरोना महामारी के समय आपसी सहयोग आवश्यक है।

4. भीलवाड़ा मॉडल

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 हॉटस्पाट्स में कोरोना वायरस महामारी के आक्रामक नियंत्रण के लिए भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा करते हुए 'कंटेनर प्लान फॉर लार्ज आउटब्रेक' शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- भीलवाड़ा राजस्थान के मेवाड़ जिले में स्थित है।
- भीलवाड़ा की तुलना चीन के वुहान शहर से की जा रही थी क्योंकि यह भारत में कोविड-19 हॉटस्पॉट के रूप में सबसे पहले उभरा था।
- भीलवाड़ा में पहला मामला 19 मार्च को आया था, परंतु मामलों की संख्या में बहुत कम समय में ही तेजी से वृद्धि हुई।

क्या है भीलवाड़ा मॉडल

- भीलवाड़ा मॉडल में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में प्रशासन द्वारा उठाए गये कदमों का जिक्र है। भीलवाड़ा मॉडल का वर्णन करने का सरल तरीका है 'रूथलेस कंटनमेंट (Ruthless Containment) अर्थात् 'निर्मम नियंत्रण'।
- भीलवाड़ा मॉडल ऑफ कंटनमेंट लगभग 6 प्रमुख चरणों में विभाजित है

जिले का अलगाव:

- प्रशासन द्वारा CRPC की धारा 144 के तहत जिले में कर्फ्यू लगाया गया।
- जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया।
- 2 अप्रैल 2020 से जिले में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग छोड़कर सभी आवश्यक सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था।

हॉटस्पाट की मैपिंग:

- हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर उनमें शून्य आवाजाही सुनिश्चित की गयी तथा इन हॉटस्पॉट में एक वफर जोन भी बनाया गया जहाँ से आवश्यक सेवाओं की पहुँच प्रभावी तरीके से हो सके।

डोर टू डोर स्क्रीनिंग:

- जिले में 22.39 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गयी तथा इंन्फ्लुएंजा-लाइक इलनेस (ILI) वाले लोगों की पहचान कर उन्हें नियमित स्क्रीनिंग के लिए चिह्नित किया गया।
- जिले भर में कुल 1,937 टीमों को तैनात किया गया था, जिन्हें 22 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 4.41 लाख घरों का सर्वेक्षण करना था।

एग्रेसीव कांटेक्ट ट्रेसिंग:

- डोर टू डोर प्रकिया के माध्यम से चिह्नित ILI वाले लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का भी पता लगाना शुरू कर दिया गया।

इंनफ्रिंजिंग क्वारेनटाइन फैसिलिटी:

- इसके लिए जिला प्रशासन ने 4 निजी अस्पतालों, 27 होटलों, 22 होस्टलों का उपयोग उच्च वायरल लोड वाले रोगियों को अलग करने में किया, जिससे वायरस घरों व इलाकों में न फैले।

मॉनिटरिंग रूरल एरिया:

- शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ायी गयी। शहरों में 24×7 कंट्रोल रूप स्थापित किये गये थे।

आगे की राह

- केन्द्र सरकार भीलवाड़ा मॉडल को लागू करने की योजना बना रही है, परंतु इसे पूरे देश में लागू करना इतना आसान नहीं होगा।
- देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि के साथ, सरकार को देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा स्थानीय प्रशासन तथा जमीनी स्तर पर गठित टीमों के सशक्तिकरण के लिए जरूरी कारवाई की आवश्यकता है।

5. भारत द्वारा AIIB एवं ADB से ऋण की मांग

चर्चा का कारण

- भारत COVID-19 का मुकाबला करने के लिए AIIB एवं ADB से $ 6 बिलियन के ऋण की मांग की है। केंद्र सरकार देश में परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक धन के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और ADB के साथ बातचीत कर रही है।
- हाल ही में कोरोना वायरस की चपेट में आये भारत को विश्व बैंक ने 76 अरब रूपये की मदद करने का प्रस्ताव किया है।
- विश्व बैंक से मिलने वाली मदद का उपयोग सुरक्षा उपकरणों की खरीद और देश के विभिन्न अस्पतालों में नए अलग वार्ड की स्थापना के लिए किया जाएगा।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB)

- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य एशिया- प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। इसे पश्चिम वर्चस्व वाले एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक (WB) की एशिया की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) :

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसम्बर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गयी थी।
- इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, अब एडीबी के पास अब 67 सदस्य हैं - जिसमे से 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं।
- एडीबी (ADB) का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था और विश्व बैंक के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है जिसमे वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है।

विश्व बैंक की आपात सहायता

- विश्व बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे विश्व को आपात सहायता देने की बात कही है।
- विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं के तहत पहले दौर में 25 देशों को 1.9 अरब डॉलर की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जबकि दूसरे दौर में 40 देशों को शामिल किया जाएगा और इसी क्रम में आगे भी सहायता राशि प्रभावित देशों को प्रदान की जाएगी।,
- दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर, अफगानिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर, मालदीव के लिए 73 लाख डॉलर और श्रीलंका के लिए 12.86 करोड़ डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दी है।
- विदित हो कि विश्व बैंक ने कहा कि उसने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से निपटने में विभिन्न देशों की मदद करने के लिए 15 महीने के लिहाज से 160 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता राशि मुहैया करायेगा।

विश्व बैंक

- विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी में है।
- विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना है।
- विश्व बैंक के कुल 189 सदस्य देश हैं। इसका आदर्श वाक्य "निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना" है।

6. मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई

चर्चा का कारण

- हाल ही में जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई (पीएमआरयू) की स्थापना की गयी।
- पीएमआरयू की स्थापना राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा की गयी है।

परिचय

- जम्मू-कश्मीर में पीएमआरयू की स्थापना के साथ ही अब देश में पीएमआरयू वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 12 हो गयी है।
- उत्तर प्रदेश, केरल, ओड़िशा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र पद्रेश में पीएमआरयू की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

पीएमआरयू

- मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई (पीएमआरयू) एवं पंजीकृत सोसाइटी है।
- यह संबंधित राज्य के 'राज्य औषध नियंत्रक' (State Drug Contoller) के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है।
- पीएमआरयू को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चों के लिए वित्त पोषित किया जाता है।

पीएमआरयू के कार्य

- पीएमआरयू सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करने में (एनपीपीए) राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और राज्य औषध नियंत्रक की मदद करता है इसके अतिरिक्त, पीएमआरयू यह भी सुनिश्चित करता है कि बाजार में दवाओं की कीमत इतनी हो कि निर्माता को भी लाभ पहुँचे और ग्राहक भी इन्हें वहन कर सकें।
- पीएमआरयू द्वारा सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि दवाओं के बारे में लागों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।
- पीएमआरयू दवाओं के सैम्पल इकट्ठा करता है और विभिन्न प्रकार के डाटा का विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करता है ताकि दवाओं का सही कीमत पहचानी जा सके और उसी अनुसार उनकी बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- पीएमआरयू दवाओं में यदि कोई विसंगति पाता है तो अपनी रिपोर्ट में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के तहत कार्यवाई की संस्तुति भी करता है।

एनपीपीए

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) फार्मास्यूटिक क्षेत्र में दवाओं आदि के मूल्यों के संबंध में विनियामक निकाय है। इसकी स्थापना भारत सरकार के प्रस्ताव के तहत 1997 में की गयी थी।
- एनपीपीए, भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आता है।
- एनपीपीए, दवाओं की कीमतों के अलावा उनकी सस्ती पहुँच एवं उपलब्धता की भी देख-रेख करता है।
- एनपीपीए द्वारा औषधि मूल्य नियंत्रण (डीपीसीओ) के तहत नियमित रूप से दवाओं की एक सूची और उनकी अधिकतम कीमत तय की जाती। नवीनतम डीपीसीओ 2013 में जारी किया गया था जिसमें 384 दवाओं की सूची है।

आगे की राह

- ऐसे समय में जबकि देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, तब पीएमआरयू द्वारा जम्मू-कश्मीर में दवाओं की ज्यादा कीमतें वसूले जाने के मामलों की निगरानी करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर जमाखोरी के कारण दवाओं की कमी जैसी समस्याओं का पता लगाये जाने का काम काफी महत्त्वपूर्ण होगा।

7. कोविड–19 टेस्ट के लिए केरल मॉडल

चर्चा का कारण

- देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के लगभग 8000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इस संदर्भ में केरल सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना परीक्षण के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल किया।
- केरल सरकार को इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की मंजूरी भी मिल गई है।

रैपिड टेस्ट क्या है?

- व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का वायरल संक्रमण हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए रैपिड टेस्ट किया जाता है।
- जब कोई रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वायरस की प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर एंटीबॉडीज जारी करता है। रैपिड टेस्ट इन एंटीबॉडीज को रक्त, सीरम या प्लाज्मा नमूनों में पता लगाकर संक्रमण की पहचान करता है।
- आमतौर पर महामारी के दौरान वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जांच के लिए यह परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह सामान्य परीक्षण है और व्यक्ति के ब्लड सैंपल से किया जा सकता है। साथ ही इसके नतीजे महज 10 से 30 मिनट में आ जाते हैं। यह काफी कम कीमत में हो सकता है।
- केरल के एर्नाकुलम जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस परीक्षण के लिए एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। ये मॉडल दक्षिण कोरिया के 'ड्राइव-थ्रू टेस्टिंग सेंटर' की तर्ज पर बनाए गए हैं।

वॉक-इन सैंपल की-ओस्क

- की-ओस्क एक केबिन है, जो सभी तरफ से बंद है और सामने एक ग्लास स्क्रीन लगी होती है। इन स्क्रीन में दो ओपनिंग होती हैं, जिसमें दो बड़े रबर ग्लव लगे होते हैं। जिस व्यक्ति का टेस्ट होना होता है, उसे ग्लास स्क्रीन के सामने बैठना होता है।
- स्वास्थ्य कर्मी सैनिटाइजर से हाथ साफ कर, डिस्पोजेबल ग्लव पहनकर दोनों रबर ग्लव में हाथ डालता है। स्वास्थ्य कर्मी और व्यक्ति के बीच कोई शरीरिक संपर्क नहीं होता है।
- इस की-ओस्क के जरिए किसी भी व्यक्ति की नाक या गले से स्वैब सैंपल, या फिर ब्लड सैंपल दो मिनट में लिया जा सकता है। इसके अलावा इसके जरिए टेस्ट के दौरान स्वास्थ्य कर्मी को पूरी PPE किट पहनने की जरूरत नहीं होती है।
- इससे स्वास्थ्य विभाग पर PPE किट खरीदने का आर्थिक दबाव भी कम होगा। पूरे देश में PPE किट की कमी चल रही है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय स्तर पर सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। इससे परीक्षण के लिए अस्पताल में जाने की जरूरत कम होगी।

आइसीएमआर का नजरिया

- इस तरह की महामारी में रैपिड परीक्षण बेहद ही कारगर सिद्ध हो सकता है, लेकिन यह सार्स-सीओवी 2 संक्रमण की पुष्टि करने वाला टेस्ट नहीं है जो कि कोरोना वायरस संक्रमण का कारक बनता है।
- आइसीएमआर ने अपने दिशानिर्देशों में साफ कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी किट की सिफारिश नहीं की जाती है। यह प्राथमिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो यह सार्स-सीओवी 2 का संकेत देता है।
- वहीं नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आने पर भी कोविड-19 के संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को सार्स-सीओवी2 वायरस की पुष्टि के लिए पॉलिमर चेन रिएक्शन (पीसीआर) टेस्ट करवाना ही चाहिए। रैपिड टेस्ट वायरल संक्रमण के 7-10 दिनों के मध्य ही पॉजिटिव आता है और उसके कई सप्ताह बाद तक पॉजिटिव रहता है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. बी.सी.जी. वैक्सीन

प्र. बी.सी.जी. (बैसिलस कैलमेट-गुएरिन) टीका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. बी.सी.जी., टीबी (यक्ष्मा/तपेदिक) जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए नवजात शिशु को दिया जाने वाला टीका है।
2. भारत के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया, दुनिया की सबसे बड़ी (BCG) वैक्सीन निर्माता है।

उपर्युक्त मे से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तरः (c)

व्याख्याः बी.सी.जी. या बैसिलस कैलमेट गुएरिन तपेदिक रोग के लिए एक टीका है। भारत में 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम शुरू हुआ था तब से इस कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। एक शोध के अनुसार यह देखा गया कि जिन मुल्कों में बीसीजी वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां कोरोना की वजह से मौत के मामलों में कमी है। पूणे स्थित सीएम इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया, दुनिया का सबसे बड़ा BCG वैक्सीन निर्माता है। ■

2. जियोफेंसिंग

प्र. जियोफेसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जियोफेसिंग एक स्थान आधारित सेवा है जिसमें एक ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जीपीएस, आरएफआईडी, वाई-फाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है।
2. जियोफेसिंग से 300 मीटर की परिधि तक सटीक जानकारी पाई जा सकती है।
3. कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने हेतु जियोफेसिंग का प्रयोग करने वाले राज्यों में केरल पहला राज्य है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः जियोफेसिंग एक स्थान आधारित सेवा है जिसमें एक ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जीपीएस, आरएफआईडी, वाई-फाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है। जियोफेसिंग से 300 मीटर की परिधि तक सटीक जानकारी पाई जा सकती है। कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने हेतु जियोफेसिंग का प्रयोग करने वाले राज्यों में केरल पहला राज्य है। अतः उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। ■

3. ऑपरेशन संजीवनी

प्र. ऑपरेशन संजीवनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत ने मालदीव में चिकित्सीय आपूर्ति के लिए एक मिशन को अंजाम दिया, जिसका नाम है 'ऑपरेशन संजीवनी' है।
2. भारत का ऑपरेशन संजीवनी, सभी सार्क देशों में भारत के विश्वास को बढ़ाएगा।
3. ऑपरेशन संकट मोचन-2016 में दक्षिण अफ्रीका से केरल के नागरिकों को वापस लाने के लिए किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। अतः उपर्युक्त में से कथन 3 गलत है। ■

4. भीलवाड़ा मॉडल

प्र. भीलवाड़ा मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भीलवाड़ा मॉडल में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में उठाये गये कदमों का जिक्र है।
2. भीलवाड़ा मॉडल ऑफ कंटेनमेंट लगभग 6 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः भीलवाड़ा मॉडल में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में उठाये गये कदमों का जिक्र है। भीलवाड़ा मॉडल ऑफ कंटेनमेंट लगभग 6 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। ■

5. भारत द्वारा AIIB एवं ADB से ऋण की मांग

प्र. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. AIIB (एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक) का लक्ष्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
2. इसका मुख्यालय नई दिल्ली (भारत) में है।
3. भारत इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है।

उपर्युक्त मे से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) चीन द्वारा शुरू किया गया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में है। चीन AIIB में अपने 27% वोटिंग शेयर के अंतर्गत प्रथम स्थान पर है। भारत 7.7 प्रतिशत के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। इसके बाद रूस 6.1% और जर्मनी 4.27% के साथ हैं। इसे पश्चिमी वर्चस्व वाले एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक (World bank) की एशिया में प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। ■

6. मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई

प्र. मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई (PMRU) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmacrutical Pricing Unit-NPPA) ने केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई (Price Monotaring and Resource Unit-PMRU) की स्थापना की।
2. जम्मू एवं कश्मीर प्रथम राज्य/संघ शासित प्रदेश बन गया है जहाँ मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई की स्थापना की गई है।

उपर्युक्त मे से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः 1 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई (Price Monotaring and Resource Unit) की स्थापना की। मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई PMRU पहले से ही 11 राज्यों में स्थापित है, जिनमें केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैण्ड, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। ■

7. कोविड-19 टेस्ट के लिए केरल मॉडल

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का वायरल संक्रमण हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए रैपिड टेस्ट किया जाता है।
2. इस टेस्ट के लिए वॉक-इनसैंपलकीओस्क के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की नाक या गले से स्वैब सैंपल, या फिर ब्लड सैंपल दो मिनट में लिया जाता है

उपर्युक्त मे से कौन सा/से कथन सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का वायरल संक्रमण हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए रैपिड टेस्ट किया जाता है। जब कोई रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वायरस की प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर एंटीबॉडीज जारी करता है। रैपिड टेस्ट इन एंटीबॉडीज को रक्त, सीरम या प्लाज्मा नमूनों में पता लगाकर के संक्रमण की पहचान करता है। आमतौर पर महामारी के दौरान वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जांच के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. नासा का नया रडार ज्वालामुखी और भूकंप की चेतावनी देगा

- हाल ही में नासा द्वारा विकसित Cubesat Imaging Radar for Earth Science (CIRES) ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की शुरुआती चेतावनी का संकेत देगा। इस राडार से उपलब्ध आंकड़े उस क्षेत्र की पहचान करने में मदद करेंगे जहां ऐसे किसी संकट के दौरान आपदा राहत पहुंचाई जानी चाहिए।
- नासा के अनुसार, CIRES एक S- बैंड इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार (InSAR) से लैस है। S- बैंड राडार के द्वारा घने जंगलों के बीच से भी पृथ्वी की सतह का चित्र लिया जा सकता है। CIRE द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र की दो राडार चित्रों को दो अलग-अलग समय पर अंतरिक्ष में एक ही स्थान से लेता है। तत्पश्चात उन दोनों चित्रों में अंतर देख कर सूचना का संग्रहण किया जाता है।

यह उपग्रह कैसे काम करेगा

- भूकंपों के लिए, CIRES के नए किस्म के रडार भूकंप के आने से पहले ही इसके खतरे को भांप सकते हैं।
- किसी ज्वालामुखी विस्फोट से पहले उभार घटना होती है। मैग्मा जमा होता है और जिसके कारण जमीन थोड़ी-सी ऊपर की तरफ उभरती है। InSAR इस उभार का निरीक्षण कर सकता है और उस विशेष क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में पूर्व-चेतावनी दे सकता है।
- अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के एक भूभौतिकीविद केली एंडरसन के अनुसार, 'यद्यपि, यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि यह भावी विस्फोट कितना लंबा या बड़ा होगा'।

नासा के बारे में

- नासा की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार का एक स्वतंत्र निकाय है। यह नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ-साथ वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष तकनीकी अनुसंधान से जुड़े सारे कामकाज संभालता है।
- नासा का उद्देश्य अवलोकन प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी की बेहतर समझ व पूरे सौर मंडल में स्थित अन्य निकायों की खोज करने के साथ-साथ भौतिकी विषयों के बारे में अनुसंधान करना है।

2. 'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' पोर्टल का शुभारम्भ

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक पोर्टल का शुभारम्भ किया है। इस पोर्टल पर अपने-अपने देश से दूर भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए विभिन्न सेवाओं से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। इस पोर्टल का नाम 'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' है और इसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायक नेटवर्क के रूप में काम करना है।
- यह पर्यटकों विशेषकर दूसरे देशों से घूमने आए पर्यटकों की बेहतरी सुनिश्चित करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है।

परिचय

- विश्वभर में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुकी है, जिसके चलते भारत समेत सभी देशों ने इंटरनेशनल हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने हेतु 24 मार्च को 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है।
- दरअसल, भारत समेत लगभग सभी देशो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के पीछे संक्रमण को फैलने देने से रोकना था, क्योंकि कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामले दूसरे देशों से लौटे यात्रियों से अधिक सामने आ रहे थे।

इस पोर्टल से लाभ

- यह पोर्टल उन पर्यटकों के लिए मददकारी होगा, जो दूसरे देशों से आकर भारत में फंस गए हैं।
- मंत्रालय के अनुसार यह 'स्ट्रेंडेड इन इंडिया पोर्टल' की शुरूआत अन्य देशों से आए और भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की कुशलता सुनिश्चित करने का प्रयास है।
- पोर्टल strandedinindia. com पर

कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर संबंधी समग्र जानकारी मुहैया कराई गई है, जो विदेशी पर्यटक किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

- पोर्टल पर विदेश मंत्रालय के नियंत्रण केंद्रों के बारे में जानकारी के साथ ही उनके संपर्क की जानकारी और राज्य अथवा क्षेत्र आधारित पर्यटन सहायता संबंधी सूचना भी उपलब्ध है।

3.मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लांच किया 'समाधान' चैलेंज

- हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में COVID -19 का मुकाबला करने के लिए एक "समाधान" चैलेंज शुरू किया है। इस ऑनलाइन चैलेंज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेटिव सेल और AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) ने फोर्ज और इनोवेटक्यूरिस के साथ मिलकर लॉन्च किया है।

मुख्य बिंदु

- "समाधान" चैलेंज का उद्देश्य छात्रों को नई खोज करने और नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना और उन समाधानों के साथ आना है जो COVID-19 से लड़ने में मदद करेंगे। चुने गए समाधान सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवाओं में लागू किए जायेंगे।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- वायरस को रोकने में सभी देशों की चुनौतियाँ एक दूसरे से भिन्न-भिन्न होती हैं। क्योंकि वायरस का प्रसार स्थलाकृति के आधार पर भिन्न होता है। इसलिए, विभिन्न देशों के सामने आने वाली चुनौतियां भी अलग-अलग हैं।

भारत के सामने चुनौतियां निम्नानुसार हैं:

- उच्च जनसंख्या घनत्व का होना।
- खराब सार्वजनिक स्वच्छता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोग सड़क पर थूकते हैं।
- वायरस की ऊष्मायन अवधि अभी तक सटीक रूप से ज्ञात नहीं है। ऊष्मायन अवधि एक व्यक्ति के संक्रमित होने और उसके लक्षण दिखने के बीच का समय अंतराल है।
- सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का प्रचार एवं प्रसार।
- वायरस के कारण लागू किया गया लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

4. अमेरिका में बाघिन को कोरोना वायरस का संक्रमण

- वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के ब्रोंक्स जू की एक खबर के मुताबिक, न्यूयॉर्क शहर के एक बाघ को कोरोनो वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। चार साल की मादा बाघ का नाम नादिया है। इसके साथ ही साथ तीन अन्य बाघ और तीन अफ्रीकी शेर में भी सूखी खाँसी की शिकायत दर्ज की गई है। ब्रोंक्स चिड़ियाघर 16 मार्च से ही जनता के लिए बंद कर दिया गया था।
- इस घटना के बाद अब भारत सहित पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। देश के सभी चिड़ियाघरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी के जरिए सभी जानवरों की 24 घंटे निगरानी का आदेश दिया गया है।
- भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देशभर के चिड़ियाघरों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लक्षण / असामान्य व्यवहार के लिए सीसीटीवी के माध्यम से 24X7 जानवरों की निगरानी करें तथा न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स जू में बाघ को हुए कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रहें।

पृष्ठभूमि

- अमेरिका में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। यह अब इंसानों से जानवरों में पहुंच रहा है, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। अमेरिका में 05 लाख 40 हजार से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। चीन में दिसंबर 2019 में पहली बार कोरोना वायरस का पता चला था। इसके बाद से विश्वभर में अबतक लगभग एक लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 3 लाख 60 हजार से ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं।

अन्य केस

- इससे पहले बेल्जियम में एक बिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। बेल्जियम के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस मामले की पुष्टि की है। इसके पहले हांगकांग में दो कुत्तों को वायरस से संक्रमित पाया गया था। हांगकांग के कृषि मत्स्य और संरक्षण विभाग का कहना था कि ये ऐसा केस था, जिसमें इंसानों से जानवरों में संक्रमण फैलने की संभावना दिख रही थी।

5. प्रतिचक्रीय पूँजी बफर (Counter Cyclical Capital Buffer – CCyB) योजना

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिचक्रीय पूँजी बफर (Counter cyclical capital buffer – CcyB) योजना के कार्यान्वयन को टाल दिया है और निर्यात से होने वाले लाभ के लिए वसूली की अवधि बढ़ा दी है।
- प्रतिचक्रीय पूँजी बफर योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 फरवरी, 2015 को आरम्भ की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि CCyB को परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर सक्रिय बनाया जाएगा।

प्रतिचक्रीय पूँजी बफर (COUNTER CYCLICAL CAPITAL BUFFER – CCyB) क्या है?

- इस का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को समय-समय पर अर्थव्यवस्था को होने वाले जोखिमों से उत्पन्न हानियों से सुरक्षित रखना है।

- इसके अंतर्गत बैंकों को उस समय के लिए पूँजी बनाये रखना होता है जब आर्थिक एवं वित्तीय परिवेश बुरी अवस्था में हो।
- इस बफर पूँजी का उपयोग, बैंक भविष्य में होने वाले घाटे के समय कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- 2007-09 में घटित वित्तीय संकट के समय प्रतिचक्रीय पूँजी बफर की परिकल्पना की गई थी और विश्व के सभी केन्द्रीय बैंकों ने सहमति से कतिपय उपाय सुझाए थे। इन उपायों को BASEL III का नाम दिया गया था क्योंकि इनकी रूप रेखा Bank of International Settlements Basel Committee के द्वारा तैयार की गई थी।

6. आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) मोबाइल ऐप

- कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घरों में जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उन पर अब सरकार नजर रखने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। इसके साथ ही तकनीक के जरिए ही कोरोना संक्रमित लोगों के मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हाल ही में 'आरोग्य सेतु' ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोग अपने आसपास कोरोना के मरीजों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
- सरकार का मुख्य उद्देश्य इस ऐप के जरिए यूजर्स की मदद करना है ताकि वे यह जान सकें कि क्या वे कोरोना से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं या नहीं। यूजर्स के स्मार्टफोन के लोकेशन डाटा और ब्लूटूथ के इस्तेमाल से संक्रमण का पता लगाया जाएगा।
- सरकार इससे पहले भी 'कोरोना कवच' नाम के मोबाइल एप को लॉन्च कर चुकी है। कोरोना ट्रैकर ऐप आरोग्य सेतु फिलहाल 11 भाषाओं में काम करेगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल हैं। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप यूजर को खुद को महामारी से बचाने के टिप्स भी देती है।

कैसे काम करती है ऐप?

- यह ऐप फोन के लोकेशन डाटा और ब्लूटूथ का उपयोग कर देखती है कि कहीं यूजर किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया है। इसे संक्रमितों का डाटाबेस के साथ जोड़ा गया है। यह ऐप लोकेशन डाटा के जरिये यूजर्स की लोकेशन की पता लगाती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सहायता से यह देखा जाता है कि यूजर किसी संक्रमित व्यक्ति के छह फीट के दायरे में आया है या नहीं।
- यह यूजर को इसके आधार पर अगला कदम उठाने की सलाह देती है। यदि यूजर हाई रिस्क एरिया में हैं तो इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट कराने, हेल्पलाइन पर फोन करने और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए सलाह दी जाती है।

कई फीचर्स से है लैस

- आरोग्य सेतु ऐप में कई और फीचर भी दिए गए हैं। इसमें दिए गए चैट बॉक्स की सहायता से आप कोरोना वायरस के लक्षण को पहचान सकते हैं। यह ऐप हेल्थ मिनिस्ट्री के अपडेट्स और भारत के हर राज्यों के कोरोना वायरस हेल्प लाइन नंबर की सूची भी देता है।
- इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु ऐप यूजर को खुद को महामारी से बचाने के कई टिप्स भी देती है। यदि कोई यूजर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो यह उसका डाटा सरकार को भेज देती है।

7. कश्मीर में नए डोमिसाइल नियम का ऐलान

- जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेट्स वापस लिए जाने के आठ महीने बाद केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नया डोमिसाइल नियम को लागू कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 15 सालों से रह रहे नागरिक इस डोमिसाइल के हकदार होंगे। इसके तहत जिन बच्चों ने सात वर्ष तक केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल होंगे। उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिल पाएंगी। ऐसे लोग अपने इलाके के तहसीलदार से मूल निवासी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
- नियमों में बदलाव के तहत राज्य में 10 साल तक सेवाएं दे चुके अखिल भारतीय सेवाओं (क्लास-ए) के अफसरों, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी बैंकों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों या केंद्र से मान्यता प्राप्त संस्थान में अफसरों के बच्चे भी मूल निवासी होंगे। जिन्हें राहत और पुनर्वास आयुक्त ने इस केंद्रशासित प्रदेश में शरणार्थी या प्रवासी का दर्जा दिया है, वे भी इस कैटिगरी में होंगे। मूल निवासियों को ही इस केंद्रशासित प्रदेश की ग्रुप-4 की नौकरियां दी जाएंगी।
- केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी विश्वास दिलाया था कि जम्मू-कश्मीर के लिए नया कानून किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर होगा। डोमिसाइल कानून 25,500 रुपये के मूल वेतन के साथ आने वाले सभी पदों पर भर्ती के लिए लागू होगा

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. कोरोना वायरस से पड़ने वाले वर्तमान प्रभाव को तो देखा जा रहा है लेकिन भविष्य में पड़ने वाले इसके कई प्रभाव अप्रत्यक्ष हैं, जो वर्तमान से भी ज्यादा विनाशकारी होंगे। इनसे निपटना मानव जाति के लिए किसी दु:स्वप्न से कम नहीं होगा। आप इससे कितना सहमत है? चर्चा करें।

2. वर्तमान की कई प्राकृतिक और मानवीय घटनाक्रम ने यह परिलक्षित कर दिया है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को अपने सार्वजनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए न कि निजी व्यवस्था को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि नागरिकों का अत्यधिक कल्याण हो सके। चर्चा करें।

3. लाकडाउन में घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों को बताते हुए, इसके प्रभाव तथा समाधान का उल्लेख करें।

4. वर्तमान में विश्व की स्थापित संस्था डब्ल्यूएचओ (WHO) पर यह प्रश्न उठ रहा है कि यह कई देशों के आँकड़ों को छूपा रहा है। क्या यह सही है कि यह किसी विशेष देश का पक्ष ले रहा है जो इसके उद्देश्यों से भिन्न है? चर्चा करें।

5. भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने में 'डिजिटल इंडिया' अभियान का कितना महत्व है? उदाहरण सहित चर्चा करें।

6. भारत कृषि प्रधान देश है। जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित करता है? उल्लेख करें।

7. भारत की वर्तमान ऊर्जा समस्या के समाधान में 'प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स' किस प्रकार सहायक है? चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा 'हीरो टू एनिमल्स अवार्ड' से सम्मानित किया गया है?

   - ओडिशा

2. इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने COVID-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए वैश्विक स्तर पर चल रहे कौन से कार्यक्रम को समर्थन दिया है?

   - हैक द क्राइसिस

3. किस राज्य सरकार ने लॉक-डाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई-पास जारी करने के लिए 'PRAGYAAM' नामक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की है?

   - झारखंड

4. किसने देश में COVID-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 'ऑपरेशन नमस्ते' नामक पहल लांच की है?

   -भारतीय सेना

5. विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस, 2020 की थीम क्या है?

   -Its Time

6. हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी मिली है?

   -चीन

7. हाल ही में, सिडबी द्वारा नये उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है?

   -स्वावलंबन एक्सप्रेस

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ

1. आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अँधा बना देगी।

   – महात्मा गांधी

2. एक सच्चा लीडर लोगों के विचारों के पीछे नहीं चलता बल्कि वो लोगों के विचारों को बदल देता है।

   – मार्टिन लूथर किंग जूनियर

3. धन को विलास के लिए खर्च करना एक प्रकार से चोरी होगी क्योंकि वह धन असहायों और जरूरतमन्दों के लिए है।

   – अरविन्द घोष

4. कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं।

   – रवीन्द्रनाथ टैगोर

5. वो हर व्यक्ति जो विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रुढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसके प्रति अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी।

   – भगत सिंह

6. वफादार और कुशल महान कारण के लिए कार्य करते हैं, भले ही उन्हें तुरंत पहचान न मिले, अंतत: उसका फल मिलता है।

   – जवाहरलाल नेहरु

7. कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रह कर नहीं हल की जा सकती है जिसपर वह उत्पन्न हुई है।

   – अल्बर्ट आइंस्टीन

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

Guiding Generations

towards making a better India

उपलब्ध कार्यक्रम

कक्षा कार्यक्रम : प्रीमियम बैच, मेंस बैच, फोकस बैच, सीसैट बैच एवं वैकल्पिक विषय

अन्य कार्यक्रम : ऑल इंडिया टेस्ट सीरिज, क्रैश कोर्स, साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (इंटरव्यू गाडेंस प्रोग्राम), पीएमआई (PMI) एवं स्टूडेंट पोर्टल

उड़ान : उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल (10+2) के ठीक बाद छात्रों के सामर्थ्य को संचार एवं परामर्श के माध्यम से समग्र रूप से सशक्त करना।

प्रवेश प्रारम्भ

नया सत्र: 2020-21

बैच आरम्भ: अप्रैल-मई 2020

अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित केंद्र पर संपर्क करें

or

Logon to : www.dhyeyaias.com

or

Call: 011-49274400

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA** 0120 4254088 | 9205336037, 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR : BIHAR SHARIF – 9507021386, PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, BIJNOR-8126670981, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूज़लेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |